राशन की चीनी महंगी कर सकेंगे राज्य

यह अधिकार राज्यों को देने के लिए कैबिनेट नोट जल्द

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में चीनी के बिक्री भाव में बढ़ोतरी का अधिकार राज्यों को देने जा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। इस समय पीडीएस में चीनी का बिक्री भाव 13.50 रुपये प्रति किलो है। इसमें वर्ष 2002 के बाद से ही कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इस समय फुटकर बाजार में चीनी के भाव 37 से 38 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं।

गत मई महीने में चीनी उद्योग को डीकंट्रोल करने के समय यह शर्त रखी गई थी कि अगले दो साल तक राज्य सरकारें पीडीएस में चीनी का आवंटन करने के लिए 32 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी की खरीदारी कर सकेंगी, जिसमें केंद्र सरकार 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकारों को करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को चीनी की खरीद महंगी पड़ रही है तथा इस बारे में वित्त मंत्री से भी बात हुई है। इसलिए केंद्र सरकार पीडीएस में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का अधिकार राज्यों को देने के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर रही है।

देश में पीडीएस के तहत चीनी की सालाना खपत करीब 27 लाख टन की होती है। चीनी उद्योग के डीकंट्रोल होने से पहले तक केंद्र सरकार चीनी मिलों से 10 फीसदी लेवी की चीनी लेती थी।

कीमतों में भारी अंतर

इस समय पीडीएस में चीनी का बिक्री भाव है 13.50 रुपये प्रति किलो

वहीं, फुटकर बाजार में चीनी के भाव 37 से 38 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं

Business Bhaskar

8/8/13